भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1952

18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

गेहूं की खरीद और एमएसपी पर भुगतान

1952. श्रीमती किरण चौधरी:

श्री मदन राठौड़:

श्री बृज लाल:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:

श्री नरहरी अमीन:

श्रीमती माया नारोलिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2025-26 के लिए राजस्थान सहित राज्य-वार गेहूं खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक कितनी वास्तविक खरीद हुई है;

(ख) किसानों तक एमएसपी भुगतान पहुंचने में लगने वाला औसत समय कितना है और आरएमएस 2025-26 में समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने गेहूं खरीद, भुगतान तथा स्टॉक की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए वास्तविक समय आधारित निगरानी तंत्र स्थापित किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2025-26 के लिए राजस्थान सहित गेहूं की राज्यवार अनुमान और खरीद की मात्रा निम्नानुसार है:

.....2/-

क्रम संख्या	राज्य	खरीद अनुमान (लाख टन में)	खरीदी गई मात्रा (दिनांक 11.03.2025 तक)
1.	पंजाब	124.00	-
2.	हरियाणा	75.00	-
3.	मध्य प्रदेश	60.00	-
4.	उत्तर प्रदेश	30.00	-
5.	राजस्थान	20.00	24.9 टन
6.	बिहार	2.00	-
7.	गुजरात	1.00	-
8.	उत्तराखंड	0.50	-
9.	हिमाचल प्रदेश	0.10	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.10	-

(ख): एमएसपी का भुगतान सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से अधिमानतः खरीद के 48 घंटे के भीतर सीधे ही किसानों के बैंक खातों में किया जाता है।

(ग): एमएसपी संचालन के तहत खाद्यान्नों की खरीद अनिवार्य रूप से राज्य खरीद पोर्टलों के माध्यम से की जा रही है, जिससे सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसानों के पंजीकरण, भूमि/फसल सत्यापन और एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किए जाने की शुरुआत के साथ इस प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता आई है। बेहतर निगरानी, समीक्षा और निर्णय लेने के लिए लगभग वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं का भंडार रखने के लिए राज्य खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खरीद खाद्यान्न पोर्टल (सीएफपीपी) के साथ एकीकृत किया गया है।

*****